(b) The names of all films will be known only some time before the Festival *i.e.* around late December 1988, early January, 1989.

शाहबाद कोआपरेटिव शूगर मिल्स का स्थापित किया जाना

260. **श्री राम नरेश यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष हरियाणा में शाहबाद कोआपरेटिव शूगर मिल क सहायता के रूप में सरकार द्वारा कर्ज दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस कर्ज की शर्तें क्या थीं तथा कर्ज की धनराशि कितनी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि संस्थान के प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस सहायता धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) हरियाणा की शाहबाद सहकारी चीनी मिल को चीनी विकास निधि से गन्ने के विकास के लिए 171.75 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया गया है । इस ऋण की राशि का भुगतान 3 वार्षिक किस्तों में किया जाना है । इस ऋण पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष है । भुगतान करने में चूक करने की स्थिति में चीनी मिल को $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देना होगा । मूलधन पर 3 वर्ष के स्थगन काल के बाद 4 वार्षिक किस्तों में ऋण की राशि वापस करनी होगी । ब्याज की अदायगी हर वर्ष करनी होगी । चीनी मिल को राज्य सरकार को सूचना प्रस्तुत करनी होती है जिसे चीनी मिल द्वारा चलाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखनी होती है। हरियाणा सरकार दिए गए ऋण की समूची राशि और उस पर देय ब्याज के प्रति राज्य सरकार की जिम्मेदारी के लिए सहमत है । ऋण की दूसरी/बाद की किस्त राज्य सरकार से संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी। राज्य सरकार की गारन्टी पर 56.89 लाख रुपये की पहली किस्त मार्च, 1987 में जारी की गई थी ।

(ग) और (घ) योजना के अनुसार हरियाणा सरकार को चीनी विकास निधि की सहायता से चीनी मिल द्वारा चलाई गई योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखनी होती है । केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया था । तथापि, योजना के कार्यान्वयन और ऋण सहायता के उपयोग में कुछ अन्तर और कमियां पायी गई थीं और ये चीनी मिल और राज्य सरकारों को बतायी गई थीं । चीनी मिल ने विभिन्न अन्तर/कमियों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जिससे हरियाणा सरकार पूरी तरह संतुष्ट थी ।

योजनाओं के ब्यौरे और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

पहला वर्ष :

योजना का नाम	वास्तविक उपलब्धियां	सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय परिव्यय	पहले वर्ष में मिल द्वारा किया गया वास्तविक खर्च
1. बीज नर्सरियां उगाना	एक उपचार यूनिट+8 एकड़	1.20 लाख रु०	1.12 लाख रु०
उन्नत किस्मों का प्रयोग करना	3200 एकड़	53.58 लाख रु०	49.10 लाख रु०
3. रतून प्रबंध		0.93 लाख रु०	
4. सिंचाई	125 नं०	7.50 लाख रु०	7.48 लाख रु०

चीनी मिल का दूसरे वर्ष के दौरान योजना-2 के अन्तर्गत आयी कमी को पूरा करने का विचार है।

Installation of High Power T.V. Station in Vizianagaram

261. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to instal a High Power Television station to cater to the needs of the Tribal people of Parvatipuram agency area in Vizianagaram district Seethampeta agency area of Srikakulam district and Gunapuram, Gudari area of Koraput district;

(b) whether it is a fact that there is a proposal to instal a High Power Television Station at Donubhai, an important Tribal village in Vizianagaram district; and

(c) if so, by when?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Parts of Vizianagaram and Srikakulam districts of Andhra Pradesh are covered by T.V. service from the high power (10KW) TV transmitter functioning at Visakhapatnam. A low power TV transmitter is envisaged to be commissioned into service at Srikakulam during 1989-90, as part of the Seventh Plan. Two low power TV transmitters one each at Koraput and Jeypore are, at present, functioning in Koraput district of Orissa. A high power (10KW) TV transmitter, under implementation at Bhawanipatna, is expected to provide service to parts of Koraput district, when commissioned into service towards the end of the Seventh Plan period. TV service to the remaining uncovered parts of the country including those of Vizianagaram and Srikakulam districts of Andhra Pradesh and Koraput district of Orissa can be carried out in a phased manner depending upon the availability of resources for this purpose in the future plans for TV expansion.